मुख्यमंत्री भजनलाल की पहल पर ''रिम्स'' स्थापना के काम को मिल रही गति

एम्स नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के बीच एम.ओ.यू. हुआ

- रिम्स की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को मिलेगी विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा
- राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाएं और सुदृढ़ होंगी

जयपुर, 07 अक्टूबर। मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा की पहल पर एम्स की तर्ज पर जयपुर में रिम्स की स्थापना के काम को प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), नई दिल्ली और राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग के बीच मंगलवार को राजस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), जयपुर की स्थापना और संचालन के लिए एक एमओयू हस्ताक्षिरत किया गया। एमओयू पर एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास और राजस्थान सरकार के चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉ. इकबाल खान ने हस्ताक्षर किए।

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीष कुमार ने बताया कि यह समझौता संस्थागत विकास पर केंद्रित है, जिसमें तकनीकी, शैक्षिणक और संगठनात्मक सहायता के माध्यम से पारस्परिक लाभ पर जोर दिया गया है, जिससे नवाचार और उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा। एम्स की वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता का लाभ लेकर रिम्स को एक अग्रणी तृतीयक चिकित्सा संस्थान के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अनुसंधान में अंतरराष्ट्रीय मानक सुनिश्चित हो सकेंगे।

एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने कहा कि एम्स अपनी संस्थागत विरासत को रिम्स जैसे उभरते उत्कृष्टता केंद्रों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह एमओयू दूरदृष्टि और विशेषज्ञता का एक सहज संयोजन है, जो राजस्थान के युवाओं और समुदायों को विश्वस्तरीय चिकित्सा शिक्षा देने के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करेगा।

चिकित्सा शिक्षा आयुक्त डॉ. इकबाल खान ने कहा कि एम्स के साथ साझेदारी रिम्स जयपुर के लिए एक परिवर्तनकारी कदम है। यह पहल चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी। साथ ही, चिकित्सा अनुसंधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य में टिकाऊ प्रगति को भी बढ़ावा देगी, जो राज्य के आमजनों को लाभान्वित करेगी। एमओयू के तहत एम्स द्वारा रिम्स के लिए साइट योजना, रोगी प्रवाह डिजाइन, नियामक अनुपालन और वास्तुशिल्प ढांचे पर मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, ताकि रिम्स में अत्याधुनिक सुविधाएं सुगमता से विकसित की जा सकें। प्रदेश में एमबीबीएस और स्नातकोत्तर शिक्षण के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन, संकाय प्रशिक्षण, विनिमय कार्यक्रम और मेंटरशिप में संयुक्त प्रयास किया जायेगा, जिससे नैदानिक और शैक्षिणक क्षमताओं का संवर्द्धन होगा। साथ ही, संगठनात्मक ढांचे, मानव संसाधन नीतियों, खरीद फ्रेमवर्क, जैव-सुरक्षा मानकों, नैतिकता समितियों और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन सेल की स्थापना में सहायता मिल सकेगी।

एमओयू के क्रियान्वयन से अनुसंधान और नैदानिक उत्कृष्टता आयेगी। संयुक्त अनुसंधान पहल, नैदानिक प्रयोगशालाएं और मानक संचालन प्रक्रियाएं बेहतर हो सकेंगी, जिससे साक्ष्य-आधारित अभ्यास और रोगी परिणामों में सुधार होगा।

प्रधानमंत्री मोदी का जीवन राष्ट्र को समर्पित : सुधांशु त्रिवेदी

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने मंगलवार को जयपुर में प्रेस वार्ता की।

जयपुर। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुशासन के 24 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामनाएं दते हुए उन्हें भारतीय राजनीति में सेवा, समर्पण और सुशासन का प्रतीक बताया।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी और तब से अब तक उन्होंने बिना किसी अवकाश के 24 वर्षों तक निरंतर राष्ट्र की सेवा की है। यह उपलब्धि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में अद्वितीय है।

- बिहार चुनावों की स्थिति पर टिप्पणी करते हुए डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि ''हाल के जनमत सर्वेक्षणों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रही है, जो वास्तविक परिणामों में बदलकर प्रचंड बहुमत में परिवर्तित होगी।''

डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का जीवन एक प्रेरणा है। उन्होंने अपने तन, मन और हर क्षण को राष्ट्र को समर्पित किया है। पहले गुजरात को विकास मॉडल के रूप में स्थापित किया और अब बीते 11 वर्षों में भारत को वैश्विक मंच पर अग्रणी आर्थिक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आर्थिक विषमताओं के बावजूद सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है।

त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारतीय राजनीति के ऐसे विलक्षण नेता हैं, जिन्होंने लगातार तीन बार मुख्यमंत्री और फिर तीन बार प्रधानमंत्री रहते हुए हर पल राष्ट्र प्रथम की भावना को जीवित रखा। यह प्रत्येक भारतवासी के लिए गर्व और गौरव का विषय है।

प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. त्रिवेदी ने बिहार चुनावों की स्थिति पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि हाल के जनमत सर्वेक्षणों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त मिल रही है, जो वास्तविक परिणामों में बदलकर प्रचंड बहुमत में परिवर्तित होगी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए पूरी स्थिरता और सामंजस्य के साथ काम कर रहा है, जबकि विपक्षी दलों में स्पष्ट नेतृत्व का अभाव और पारिवारिक कलह साफ नजर आ रही है। डॉ. त्रिवेदी ने विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' पर कटाक्ष करते हुए कहा कि यह गठबंधन अंतर्विरोधों से घिरा हुआ है – ना केवल दलों के बीच, बल्कि पार्टी के भीतर और नेतृत्वकर्ता परिवारों के भीतर भी। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, जो खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं, उनके पास क्षमता नहीं है, और जो खुद को प्रधानमंत्री इन वेटिंग कहते हैं, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि उनका नेता कौन है।

युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ने पर विशेष फोकस

'सहकार सदस्यता अभियान' के तहत मंगलवार को जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया।

- ''सहकार सदस्यता अभियान'' के लिए 3207 पैक्स के स्तर पर हो चुका शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन

जयपुर । राज्य सरकार द्वारा 2 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे ''सहकार सदस्यता अभियान'' के अंतर्गत मंगलवार तक प्रदेश में 3207 पैक्स के स्तर पर शिविरों का सफलतापूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से सहकारी समितियों की सदस्य संख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है तथा अभियान के अंतर्गत प्रावधित किये गए अन्य कार्य भी सुगमतापूर्वक सम्पन्न हो रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्रदेश में 630 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत अब तक 959 नवीन पैक्स के गठन हेतु प्रस्ताव सहकारिता विभाग को प्राप्त हो चुके हैं तथा 1076 पैक्स एवं केवीएसएस द्वारा गोदाम निर्माण हेतु भूमि चिह्नीकरण की कार्यवाही सम्पन्न की जा चुकी है। वहीं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 18 हजार 595 कृषकों की आधार सीडिंग तथा 8,419 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य किया गया है। अभियान के अंतर्गत युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोडने का कार्य तीव्र गति से जारी है।

जबकि, प्रतिदिन बडी संख्या में जनसाधारण को प्रस्तावित नवीन सहकारी अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी भी प्रदान की जा रही है। अब तक लगभग 2.50 लाख लोगों को नवीन सहकारी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी प्रदान की जा चुकी है। अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं एवं महिलाओं को सहकारी समितियों से जोडने पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इसके लिए शैक्षिणक संस्थाओं, एनजीओ, राजीविका, हिन्दुस्तान स्काउट एंड गाइड आदि का सहयोग लिया जा रहा है। मंगलवार को जयपुर के सेंट विल्फ्रेड कॉलेज में 'सहकार सदस्यता अभियान' के अंतर्गत युवाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस दौरान सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने विद्यार्थियों को सहकारिता के विभिन्न आयामों एवं विभाग की कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान लगभग 2,000 छात्र-छात्राओं से सदस्यता फॉर्म भरवाये गए। अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) संदीप खण्डेलवाल, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (जयपुर खण्ड) मदनलाल गुर्जर, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जयपुर के प्रबंध निदेशक दिनेश कुमार शर्मा एवं उप रजिस्ट्रार जयपुर (शहर) शिरीष वि. चान्दे इस दौरान मौजूद रहे।

विद्युत प्रसारण निगम और एम.एन. आई.टी. के बीच करार

जयपुर। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर और राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा संचालित स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, जयपुर के बीच विद्युत क्षेत्र में नई तकनीक अपनाने के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

इस समझौते का उद्देश्य ज्ञान साझाकरण, अनुसंधान एवं विकास, कौशल संवर्द्धन तथा क्षमता निर्माण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष अजिताभ शर्मा ने बताया कि यह समझौता संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण, छात्र इंटर्नशिप, कार्यशालाओं एवं फैकल्टी, उद्योग, संवाद जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा और उद्योग के बीच सम्बन्धों को सुदृढ़ करेगा तथा तकनीकी उत्कृष्टता एवं राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र के भविष्य की चुनौतियों के रूप मे भी तैयार करेगा।

अब एस.डी.ओ. व मेला अधिकारी भी जारी कर सकेंगे विशेष परमिट

- ऊंट परिवहन को लेकर नए नियमों का नोटिफिकेशन जारी
- कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने दिए आदेश

जयपुर । राजस्थान से ऊंटों को अन्य राज्यों में ले जाना अब और भी आसान हो गया है, इसके लिए पशुपालन विभाग ने पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री श्री जोराराम कुमावत से नियमों की स्वीकृति लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ऊंटपालकों को निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से ऊंट ले जाने की अनुमति होगी। कुमावत ने कहा कि राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 2015 में ऊंट को चराई, खेती डेयरी और पशु मेलों में भाग लेने के लिए राज्य से बाहर ले जाने का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से महिलाओं को मिला खेती में नया संबल

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने महिला कृषकों को सशक्त बनाने के लिए खरीफ 2025 सीजन में निःशुल्क बीज मिनीकिट वितरित किए हैं।

मूंग, मोठ, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों के कुल 27,95,337 मिनीकिट विभिन्न योजनाओं के तहत किसानों तक पहुँचाए गए हैं। इनमें से बड़ी संख्या में किट महिलाओं को प्रदान की गई हैं।

महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास

जयपुर । एससी, एसटी मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने आपसी विवाद के चलते परिचित महिला की हत्या करने वाले अभियुक्त सोनू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी मोहन लाल जाट ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने महिला की हत्या करने जैसा गंभीर अपराध किया है। ऐसे में उसके प्रति नरमी नहीं अपनाई जा सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मामले में संजय साहू ने 23 दिसंबर, 2018 को खोह-नागोरियान थाने में रिपोर्ट दी थी। जिसमें कहा कि वह दोपहर को वह दुकान से लूनियावास खाना खाने जा रहा था। मंगल बाजार मैदान के पास उसे काफी भीड नजर आई। उसने पास जाकर देखा तो पेड के नीचे महिला की लाश पडी हुई है और साडी खून से सनी है। इस पर उसने अपने मोबाइल से पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी थी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के एक गवाह मोहन ने अदालत को बताया कि मृतका प्रेम देवी के पति की मौत होने के बाद अभियुक्त उसके घर आने लगा था।

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने की जनसुनवाई

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन अपनी विभिन्न समस्याएं लेकर पहुंचे।

जनसुनवाई के दौरान दिया कुमारी ने प्रत्येक व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। जनता ने सड़क, पानी, बिजली, पेंशन और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं रखीं। उपमुख्यमंत्री ने मौके पर उपस्थित संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्हें समस्या समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। दिया कुमारी ने कहा कि सरकार जनता के साथ है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सरकार की प्राथमिकता है।

ब्रिटिश संसद पहुंचे देवनानी, अजमेर की ऐतिहासिक पेंटिंग भी देखी

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अपने लंदन प्रवास के दौरान ब्रिटिश संसद का भ्रमण किया। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमंस और हाउस ऑफ लार्ड्स की कार्यप्रणाली और संसदीय परंपराओं को करीब से समझा। उन्होंने वेस्टमिंस्टर हॉल और सेंट्रल लॉबी का अवलोकन करते हुए कहा कि हालांकि ब्रिटेन की संसदीय परंपराएं पुरानी हैं, पर भारत का लोकतंत्र आज विश्व का सबसे बड़ा और सुदृढ़ लोकतंत्र है। इस अवसर पर देवनानी ने सेंट स्टीफन हॉल में लगी सर थॉमस रॉ एट द कोर्ट ऑफ अजमेर 1614 की ऐतिहासिक पेंटिंग को भी देखा। उन्होंने कहा कि यह चित्र भारत-ब्रिटेन के गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है।

इकोलॉजिकल जोन में धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, जे.डी.ए. प्रशासन मौन!

आगरा रोड पर जामडोली क्षेत्र में कृषि भूमि पर काटी जा रही है अवैध कॉलोनियां

आगरा रोड पर जामडोली चौराहे स्थित विरासत विहार में अवैध निर्माण कार्य जोरों पर है।

जयपुर (कासं)। राजधानी में आगरा रोड स्थित इकोलॉजिकल जोन में इन दिनों अवैध कॉलोनियां काटकर उनमें धडल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे है। इसके बावजूद जे.डी.ए. की प्रवर्तन विंग यहां कार्रवाई के बजाय चुप्पी साधे बैठी है।

बताया जा रहा है कि जामडोली और उसके आसपास के क्षेत्र में कृषि भूमि का रूपांतरण करवाये बिना ही गृह निर्माण सहकारी समितियों के बैकडेट के पट्टों की आड़ में धल्ल्ले से कॉलोनियां बसाने का खेल चल रहा है। यहां भू-माफियाओं और बिल्डरों के गठजोड़ के कारण रातोंरात ही अवैध कॉलोनियां बस रही है, परंतु जेडीए प्रशासन तमाम शिकायतों के बावजूद भी यहां चुप्पी साधे बैठा है।

- गृह निर्माण सहकारी सोसायटियों के बैक डेट के पट्टे देकर लोगों को ठग रहे हैं भू-माफिया और बिल्डर

सूत्रों ने बताया कि आगरा रोड पर जामडोली चौराहे पर केशव विद्यापीठ के नजदीक 1 बीघा ज़मीन पर अवैध कॉलोनी ''विरासत विहार'' में भी पुनः अवैध निर्माण जोरों पर है। यहां जेडीए की टीम ने करीब 4 महीने पहले अवैध निर्माण कार्य रुकवाया था। इसके बाद करीब 3 महीने तक सब कुछ काम बंद रहा, परंतु नवरात्रि और दशहरे की छुट्टियों की आड़ में अब यहाँ तेज़ी से निर्माण कार्य पुनः शुरू हो गए।

भू-माफिया और बिल्डर लोगों को सस्ते मकान देने की आड़ में यहां तेजी से मकान बनाने में जुटे है। लोगों से एडवांस बुकिंग राशि लेकर दीपावली पर मकान का पजेशन सौंपने के दावे किए जा रहे है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड की गई सोसायटियों से फ़र्ज़ी बैक डेट के पट्टे दिए जा रहे है। इसके बावजूद जेडीए का ज़ोन 10 प्रशासन यहाँ सख़्ती से कार्रवाई नहीं कर रहा।

76 हजार किलो संदिग्ध खाद्य पदार्थ जब्त

- राजस्थान में मिलावटखोरी पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने त्यौंहारी सीजन के मद्देनज़र मिलावट के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत अब तक प्रदेशभर में 76283 किलोग्राम संदिग्ध या मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है, जबकि 58,780 किलोग्राम सामग्री को नष्ट किया जा चुका है। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा 'सिर्फ रोशनी ही नहीं, बल्कि प्रत्येक थाली भी हो सुरक्षित' थीम के तहत संचालित की जा रही है, जिससे त्योहारों के दौरान आमजन को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जा सकें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि अभियान की निगरानी स्वयं मुख्यमंत्री कर रहे हैं और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में पूरे राज्य में सघन निरीक्षण किए जा रहे हैं। मिठाई, घी, तेल, मावा, डेयरी उत्पाद और खाद्य रंग जैसे उत्पादों के साथ-साथ इनके निर्माण में उपयोग होने वाले कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

एक सितंबर से अब तक कुल 2835 निरीक्षण किए जा चुके हैं, जिनमें 2556 प्रवर्तन जांचें शामिल हैं। इसके साथ ही 3,520 नमूनों की जांच के लिए टीमें फील्ड में भेजी गईं। यह कार्रवाई उन विक्रेताओं और निर्माताओं के खिलाफ केंद्रित है जो दूध, खोया, खाद्य तेल और घी जैसे उच्च मांग वाले उत्पादों में मिलावट करते हैं।

विभाग की ओर से जहां आवश्यक पाया गया, वहां सुधार नोटिस जारी किए गए हैं और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि राज्यभर में चल रहे इस अभियान का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मिठाई निर्माताओं और खाद्य व्यवसायियों के लिए स्वच्छता, भंडारण तथा शुद्ध कच्चे माल के उपयोग पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध या अस्वच्छ खाद्य गतिविधि को देखें तो तत्काल इसकी सूचना एफएसएसएआई के फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप या स्थानीय नियंत्रण कक्ष में दर्ज कराएं, जिससे मिलावटखोरी के खिलाफ जारी इस मुहिम को और अधिक सशक्त बनाया जा सके।

एस.के.आई.टी. में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम पर पांच दिवसीय वर्कशॉप का आगाज

जयपुर (कासं)। स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोथन (एसकेआईटी) जयपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के आईई(आई) छात्र अध्याय द्वारा ''ड्राइविंग द फ्यूचरः पावर, मोबिलिटी एंड इंटेलिजेंस (बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम)'' विषय पर पाँच दिवसीय हैंड्स-ऑन वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ।

कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. अंकुश टंडन, विभागाध्यक्ष (इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग) द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. टंडन ने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सतत ऊर्जा समाधान के विकास में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने विद्यार्थियों से सक्रिय भागीदारी करने और आधुनिक ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की व्यवहारिक समझ विकसित करने का आव्हान किया। कार्यशाला के संयोजक जितेन्द्र सिंह, जिनेन्द्र राहुल तथा डॉ. सुमन शर्मा, एवं सह-संयोजक दिनेश कुमार ने आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सह-संयोजक दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों को बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम के संतुलन और तीव्र चार्जिंग की प्रक्रिया के महत्व को समझाया। उन्होंने बताया कि कैसे उचित बैलेंसिंग बैटरी की कार्यक्षमता और जीवनकाल को बढ़ाती है। साथ ही, उन्होंने प्रायोगिक प्रदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों को बैटरी प्रबंधन की वास्तविक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। उद्घाटन सत्र के साथ ही कार्यशाला की शुरुआत विभिन्न प्रायोगिक गतिविधियों, डेमो एवं प्रशिक्षण सत्रों से हुई, जिनमें बैटरी पैक डिज़ाइन, चार्ज-डिस्चार्ज नियंत्रण तथा स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। विभाग के अनेक विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।